International Journal of Education and Science Research Review

E-ISSN 2348-6457

Volume-10, Issue-6 Nov-Dec-2023 P-ISSN 2349-1817

www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में बढ़ते शहरीकरण का ग्रामीण विकास पर प्रभाव

सौरभकुमार*

एम०ए० (जे०आर०एफ०) भूगोल-शोध छात्र, आर०आर०पी०जी० कॉलेज, अमेठी, उ०प्र०

डॉ० अर्जुन प्रसाद पाण्डेय**

(असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष भूगोल विभाग, रणवीर राणजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अमेठी, उ०प्र०)

संक्षेपण

यह अध्ययन विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रगति को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना है। विकास का मुख्य लक्ष्य हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाना और समाज में असमानता को कम करना है। विकास के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संसाधनों का संतुलित उपयोग आवश्यक है। इस अध्ययन में, विकास की प्रक्रिया के दौरान सामाजिक संघर्षों और असमानताओं के बढ़ने की चर्चा की गई है, जिससे प्रशासकों और नीति नियोजकों को विकास योजना नीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पैदा होती है। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तिगत, क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रगति शामिल है और इसके लिए विभिन्न संगठनों के बीच सहयोग आवश्यक है। ग्रामीण और शहरी विकास की रणनीतियों पर भी चर्चा की गई है, जिसमें कृषि और उद्योग के बीच समन्वय की कमी और गैर-कृषि गतिविधियों के विकास को दर्शाया गया है। इस अध्ययन में भारत में शहरीकरण और इसके आर्थिक विकास से संबंधित आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें इजरायली रणनीति और भारत सरकार की अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं का उल्लेख है। इन पहलों का उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अवसरों को बढ़ाना है।

प्रमुख शब्द

सामाजिक और आर्थिक विकास, शहरीकरण और ग्रामीण प्रगति, संसाधन प्रबंधन, असमानता और सामाजिक संघर्ष, विकास नीति और योजना

परिचय

विकास समाज के सभी वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका लक्ष्य सामूहिक प्रगति हासिल करना है। विकास का एक प्रमुख उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में सामाजिक और आर्थिक सुधार लाना और समाज के भीतर असमानता को दूर करना है। विकास को फलने-फूलने के लिए सभी क्षेत्रों में विकास पहलों का सफल कार्यान्वयन और प्रभावी योजना आवश्यक है। विकास के वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का संतुलित उपयोग आवश्यक है। हालाँकि, यह अक्सर देखा गया है कि इस प्रक्रिया के दौरान, समाज के कुछ वर्ग अमीर हो जाते हैं जबकि अन्य गरीब हो जाते हैं, जिससे वंचितों में वैराग्य और मोहभंग की भावना पैदा होती है। स्वतंत्रता के बाद सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अनेक योजनाओं के कार्यान्वयन के बावजूद, व्याप्त असमानताओं के कारण सामाजिक संघर्षों में वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, प्रशासकों, नीति नियोजकों और शिक्षाविदों को विकास योजना नीतियों पर पुनर्विचार और पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग और समुदाय तक पहुंच सके। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तिगत, क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति शामिल है, जिसके लिए कानूनी, प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक संगठनों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है। हालाँकि, विकास की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है, क्योंकि विभिन्न विचारधाराओं के आधार पर इसकी अलग-अलग व्याख्या की जाती है। इस मामले पर विद्वान अलग-अलग राय रखते हैं, लेकिन यह व्यापक रूप से सहमत है कि किसी व्यक्ति के जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार उनके समग्र विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

नगरीकरण और गा्रमीण विकास

जबकि ग्रामीण क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था से संचालित होते हैं, शहरी क्षेत्र व्यापार और औद्योगिक क्षेत्रों पर निर्भर होते हैं। हालाँकि, कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने और मजदूरी दरों को बढ़ाने से ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवासन को कम किया जा सकता है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच समन्वय की कमी के साथ-साथ बड़े किसानों के पक्ष में मुनाफे के असमान वितरण ने कृषि के विकास में बाधा उत्पन्न की है। कृषि में नई तकनीकों की शुरुआत और ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित करने से कृषि और उद्योग के बीच की खाई को पाटने में मदद मिल सकती है। शहरी और ग्रामीण विकास की मुख्य रणनीतियाँ औद्योगिक और कृषि विकास के इर्द-गिर्द घूमती हैं। शहरों में उद्योग स्थापित करके, शहरी क्षेत्र विकास के ध्रुव के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिससे समग्र विकास में तेजी आ सकती है। इसके

साथ ही, पूंजी निवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने से उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, उचित विपणन चैनलों की कमी के कारण अक्सर किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। परिणामस्वरूप, शहरी क्षेत्रों को उच्च कृषि उत्पादन से अधिक लाभ होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से केवल सीमित लाभ ही मिलता है। शहरीकरण और देश के आर्थिक विकास के बीच संबंध शहरीकरण की वृद्धि दर में स्पष्ट है। शहर भौतिक बुनियादी ढांचे, वित्तीय सेवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों को अक्सर गरीबी, बेरोजगारी और कम उत्पादक आबादी जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है। भारत में, शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, संयुक्त राष्ट्र की विश्व शहरीकरण संभावना रिपोर्ट 2018 में कहा गया है कि 34 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है, 2011 की जनगणना के बाद से 3 प्रतिशत की वृद्धि। यह वृद्धि 2031 तक 6 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है और 2051 तक देश की आधी से अधिक आबादी शहरों में रहने की उम्मीद है। कृषि और उद्योग को एकीकृत करने की इजरायली रणनीति एक उदाहरण के रूप में कार्य करती है। इज़राइल में, कुशल कृषि उत्पादन विधियों को अपनाने के साथ-साथ, ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गईं। प्रारंभ में, इन इकाइयों ने मुख्य रूप से कृषि से संबंधित सेवाओं और उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण और विनिर्माण उपकरण। इनमें से कई उद्यम पूरी तरह या आंशिक रूप से किसानों के स्वामित्व में थे। समय के साथ, औद्योगिक उद्यमों का दायरा विस्तारित होकर गैर-कृषि गतिविधियों जैसे आभूषण निर्माण और मिट्टी से संबंधित उद्योगों को भी शामिल कर लिया गया। चुनौतियों का समाधान करने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) जून 2015 में लॉन्च किया गया था। इस पहल का लक्ष्य देश भर के 500 शहरों में बुनियादी सेवाओं, जल आपूर्ति, सीवरेज, परिवहन और पार्कों को बढ़ाना है। देश। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट सिटी मिशन योजना शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन में विकास के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं की गहराई से जांच की गई है, जिसमें मुख्य जोर समाज के हर वर्ग की समग्र प्रगति पर है। विकास की प्रक्रिया में संसाधनों का संतुलित उपयोग और सभी सामाजिक समूहों को विकास के लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया है। इसमें शहरीकरण और ग्रामीण विकास के बीच की खाई को पाटने की आवश्यकता को भी उजागर किया गया है, जिससे दोनों क्षेत्रों में समान रूप से विकास सुनिश्चित हो सके। अध्ययन यह भी बताता है कि कैसे विकास की प्रक्रिया में असमानता और सामाजिक संघर्ष की वृद्धि ने प्रशासकों और नीति निर्माताओं को विकास योजनाओं के पुनर्मूल्यांकन की दिशा में धकेला है। इसके अतिरिक्त, शहरी और ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न

रणनीतियों और सरकारी पहलों का वर्णन भी किया गया है, जिसमें अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन निष्कर्षों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि विकास एक बहुआयामी और जटिल प्रक्रिया है जिसकी सफलता विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों के बीच संतुलन और सहयोग पर निर्भर करती है।